away from Mattannur. Due to the lack of opportunities, for affordable education under the CBSE Board, the parents from the hilly region of Kannur send their children to private schools. Since there are many Central Government and State Government offices near the area, a KV would be immensely helpful to a large number of aspiring students. This would provide affordable education for the children of inter-State migrant workers as well. There is adequate land available for setting up a Kendriya Vidyalaya in Mattannur. Keeping in view the urgency and importance of the matter, I humbly request the Union Government to take necessary steps to open a Kendriya Vidyalaya in Mattannur.

Demand for construction of elevated double rail line from Haridwar to Dehradun and construction of over bridge at open railway crossing

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): महोदय, देश मे रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके निरंतर सुधार, सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है, जो प्रसंशनीय है।

पूरे देश में, विशेषकर उत्तराखंड के देहरादून व हरिद्वार जिले से बहुत सी रेल निकलती हैं, जो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार – देहरादून के मध्य जंगल क्षेत्र से सिंगल लाइन आती है, जिसकी स्पीड भी वन्य जीव क्षेत्र की वजह से बहुत कम है। ऐसे मे उस पर ऐलीवेटेड डबल बड़ी रेल लाइन की बहुत ज़रूरत है, जिससे ज्यादातर ट्रेन हरिद्वार से देहरादून पहुंच सकें व उसमें समय भी कम लगे।

बहुत सी रेलवे क्रासिंग्स हैं, जो आज भी खुली हैं, जहां आम रास्ता है। इनमें से कई पर बैरियर सुविधा है, कई मानव रहित हैं, यहां पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं निरंतर बनी रहती हैं व समय-समय पर दुर्घटनाएं हुई भी हैं, जिसमें लोगों की जानमाल की हानि हुई है।

मै सरकार से मांग करता हूं कि उत्तराखंड के हरिद्वार व देहरादून के मध्य एक बड़ी ऐलीवेटेड रेलवे लाइन का निर्माण हो व ऐसे रेलवे क्रासिंग्स, जहां अंडरपास नहीं है, वहां एक अंडरपास या आरओबी बनाया जाए, जिससे लोगों को सुविधा हो व भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

Demand for reservation counter and stoppage of trains at Kharar Railway Station in Punjab

श्री सतनाम सिंह संधू (नामनिर्देशित): महोदय, ऐतिहासिक खरड़ शहर पंजाब का एक महत्वपूर्ण gateway है। कुछ समय में इसकी आबादी तेज़ी से बढ़ी है और यह एक बड़े educational और economic hub के रूप में उभरा है। खरड़ और आसपास की आबादी 10 लाख से अधिक है। इसके बावजूद, लंबी दूरी की कई ट्रेनें यहां नहीं रुकती हैं।

महोदय, नागरिकों की मांग है कि खरड़ रेलवे स्टेशन पर कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव किया जाए और एक आरक्षण काउंटर स्थापित किया जाए। निवासियों द्वारा इन ट्रेनों को रोकने की

मांग है। खरड़ रेलवे स्टेशन पर Up and Down के क्रम में नांदेड़-अंबाला छावनी; बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर; वैष्णोदेवी-ऋषिकेश; कालका-वैष्णोदेवी; देहरादून-अमृतसर और सहरसा-अमृतसर का ठहराव किया जाए।

महोदय, खरड़ की पवित्र भूमि पर प्रभु श्री राम के चरणों की धूल बसी हुई है। उनके दादा जी राजा अज्ज के नाम पर मंदिर और सरोवर की वजह से खरड़ श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। साथ ही, महाभारत में भीम के पुत्र घटोत्कच का भी जन्म यहीं घरुआन गाँव में हुआ था। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबज़ादों की शहादत का बदला भी यहीं लिया था। खरड़ सिखों के सातवें और नौवें गुरु साहिबान की चरण छोह प्राप्त धरती भी है। इन ट्रेनों को खरड़ में रुकवाना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभकारी होगा, बल्कि यह अमृतसर से लेकर खरड़ तक की यात्रा को pilgrimage circuit में बदल सकता है। इससे न सिर्फ खरड़ का विकास होगा, बल्कि पूरे पंजाब में economic और tourist activities में तेज़ी आ सकेगी। अतः मेरी सरकार से यह माँग है की इस पर ध्यान दिया जाए।

Need to establish a Millet Board in Bhubaneswar

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I rise to bring to the attention, the urgent need to establish a Millet Board in Bhubaneswar, Odisha. As the world's largest millet producer, India contributed 38.4 per cent of global production, totalling 17.32 million tonnes in 2022-23. Odisha has seen a 125.7 per cent production surge since launching the Odisha Millets Mission (now Shree Anna Abhiyan) in 2017, with output projected to reach 226,972 tonnes in 2024. Despite this remarkable progress, our country still lacks an institutional framework to support farmers, drive research, and strengthen market linkages.

Establishing a dedicated Millet Board, on the lines of Tea Board or Coffee Board, is essential to boost production, processing and farmer support through financial aid, quality seeds, and advanced techniques. This board would bolster R&D, value addition, and supply chains, ensuring fair pricing and sustainable market growth. With rising national and global demand for millets due to their nutritional and environmental benefits, such an institution would play a crucial role in policy coordination, export promotion, and the overall growth of the millet economy.

Given Odisha's success in millet production and its commitment to agricultural innovation, Bhubaneswar stands as the ideal location for this initiative. A Millet Board would reinforce India's global leadership in millet cultivation while significantly benefiting farmers and rural communities.

I urge upon the Government to take immediate steps to establish a Millet Board in Bhubaneswar, ensuring that this resilient and climate-friendly crop receives the institutional support it truly deserves.